[Shri Y. B. Chavan]

other is the CPI(M)—the Marxist Communists. But popularly in all our conversations we refer to them as Right Communists and Left Communists. I am making a factual statement.

Regarding the other point, if the Parliament gives any direction to this Government the Government will have to find out ways to implement it. How to implement it is a matter for consideration. I really do not know.

श्री रवि राय (पुरी) : नक्सलबाड़ी कम्युनिस्ट पार्टी भी बन गई है ।

SHRI Y. B. CHAVAN : So, this is my position. On the merits, I personally feel that banning of parties is not the right way of doing things in politics.

MR. SPEAKER : I do not want to go into the legality of it and give a ruling. I would request the hon. Member in whose name this resolution stands to tell me what he has to say on these points that have been raised. He may say that he has committed a mistake. After hearing the Home Minister I do not know what he will say.

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो यह प्रस्ताव लैफ्ट कम्युनिस्ट पार्टी को अवैध घोषित करने के बारे में रखा है, यह एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है । मैं इस सम्माननीय सदन के सामने सभी सदस्यों से कहना चाहता हूं कि मेरे नम्र निवेदन को दल-बन्दी से ऊंचे उठ कर विचार करें, क्योंकि प्रस्ताव का सम्बन्ध पार्टी पोलिटिक्स से नहीं है बल्कि इसका सम्बन्ध देश की एकता, अखण्डता सुरक्षा और प्रजातन्त्र की रक्षा से है । इस प्रस्ताव पर एतराज करने वाले कुछ भी कहें, पर मैं निवेदन करूंगा कि वे मेरे तथ्यों को जो कि मैं रखने वाला हूं, उन को सुन लें और यदि उनमें वजन न हो, सच्चाई न हो, झूठा साबित कर सकें . . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । इस सदन का सदस्य होने के नाते इस प्रस्ताव पर मुझे स्वतन्त्रता से बोलने की इजाजत दीजिये, क्योंकि सदन की मर्यादा का विशष ध्यान रखने वाले . . . . (व्यवधान) . .

MR SPEAKER : I want him to give his opinion about the points of order raised and not to give his speech on the resolution.

श्री प्रेम चन्द वर्मा : मैं वही कह रहा हूं । मैं प्रस्ताव पर बोल रहा हूं, मैंने प्रस्ताव मूव किया हुआ है ।

MR SPEAKER : Then I have to give my ruling. I have considered all the points that have been raised. As the Home Minister himself has said, though the understanding of the people may be 'Left Communists' and 'Right Communists', the correct way of addressing them is 'Communist Party of India' and 'CPI(M)' or 'Marxist Communist'. I do not also accept the suggestion that the resolution cannot be discussed. After all this House has a right to discuss any resolution. Supposing tomorrow the Government takes some action against some party, then has not this House a right to discuss it. Therefore, I am not prepared to accept that this House has no right to discuss. This is the forum to discuss. If you drop discussion in this House, then you can discuss it in the streets. I would only suggest to the hon. Member that if there is some mistake that has crept in he can amend it and then bring it before this House after giving fresh notice. We shall now go to the next item.

16·45 Hrs.

RESOLUTION RE QUITTING THE COMMONWEALTH

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि--

> "यह सभा दक्षिण रोडेशिया में आयन स्मिथ की गैर-कानूनी सरकार द्वारा स्वतन्त्रता-सेनानियों को फांसी दिये जाने की निन्दा करती है और भारत सरकार से अनुरोध करती है कि वह आयन स्मिथ की गैर-कानूनी अल्पसंख्यक सरकार के विरुद्ध ब्रिटेन की सरकार की निष्क्रियता की दृष्टि से राष्ट्रमण्डल से तुरन्त अलग हो जाये ।"

16·45 Hrs.

[MR DEPUTY SPEAKER *in the Chair*

उपाध्यक्ष महोदय, रोडेशिया के मामले पर और कोमनवेल्थ से बाहर आने के मामले

पर इस सदन में इसके पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है । मगर जो चर्चा आखरी बार इस मसले पर हुई थी, उसका जिक्र करते हुए मैं अपने विचारों को सदन के सामने पेश करना चाहता हूं । 24 सितम्बर को, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में बहस चली --श्री भागवत झा आजाद के प्रस्ताव पर, जो पाकिस्तान के आक्रमण के बाद यहां पेश किया गया था । इंग्लिस्तान का उस वक्त जो रुख था--हिन्द-पाक लड़ाई के बारे में--आम तौर पर हिन्दुस्तान के बारे में--उसकी निन्दा सभी दलों के प्रतिनिधियों ने इस सदन में की थी और सरकार से अनुरोध किया था कि इस मसले को लेकर कामनवेल्थ से हिन्दुस्तान बाहर आ जाये । मगर वह बहस अधूरी रही और किसी कानून के मुद्दे को लेकर उस बहस को पूरा नहीं होने दिया । मगर रोडेशिया के मामले पर, उपाध्यक्ष महोदय, उससे पहले 12 नवम्बर को--यानी रोडेशिया के अपने अलग अस्तित्व के 11 नवम्बर को एलान करने के दूसरे दिन--इस सदन में श्री मधु लिमये के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर लम्बी बहस चली थी और उस बहस के दरमियान उस वक्त के हमारे विदेशी विषयक मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने कई आश्वासन इस सदन में दिये थे तथा सरकार की ओर से कई निवेदन भी यहां पर किये गये थे । मैं, उपाध्यक्ष महोदय, 12 नवम्बर की सदन की रपट को ले आया हूं । जिसमें से उस वक्त सरकार की ओर से विदेश मन्त्री द्वारा कही हुई बातों को आपके सामने पेश करना चाहता हूं । मधु लिमये के प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वर्ण सिंह साहब बोले थे :

> "I have said very clearly that we will support all efforts and we will give all-out support in pursuit of the efforts that will be made by the African population of Rhodesia to meet the situation. In this respect I have also said that we will remain in touch with all friendly countries and this is a matter which is much more serious. We should not regard this purely as a sort of a propagandist move. I anticipate a real conflict between the races in Africa and the Organisation of African Unity, I am sure, will take the initiative in this respect and we should extend all possible support to them to tackle this very difficult situation."

यह 12 नवम्बर का विदेश मन्त्री का कहना है ।

आगे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वर्ण सिंह साहब ने ऐसा कहा :

> "I would like to say that I have full confidence that we will go much beyond the British Government in this respect because, as I have said already, the British Government should have taken some more stiff actions at an earlier stage. It is really their shillyshallying with the problem that has resulted in this situation. Therefore they are taking some actions but they are very belated actions. A good deal of more stiff action should have been taken before Mr. Smith declared independence or seized illegal power."

और आगे बढ़ कर स्वर्ण सिंह साहब यह बोले :

> "Our Prime Minister took a very clear and strong stand on this issue at the time of the last Prime Ministers' Conference that was held only a few months ago. We have all along been pursuing this matter with the British Government and we have not left them in any doubt about our strong feelings in this respect. The British Government have always been giving the impression that they will do their best to prevent the emergence of a situation which has now actually emerged."

दो बातें उस वक्त की बहस से सदन के आई थीं । एक तो हिन्दुस्तान की सरकार को यह जानकारी थी कि रोडेशिया के सफेद चमड़ी के लोग वहां एक अलग ही स्वतन्त्र सरकार बना कर इंग्लिस्तान से दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं । और जो परिस्थिति उससे निर्मित होने वाली थी उसके बारे में इंग्लिस्तान की सरकार से कुछ अपेक्षा हिन्दुस्तान की सरकार ने की थी मगर वह अपेक्षा भंग हुई थी ।

[श्री जार्ज फरनेन्डीज]

दूसरी बात इस बहस से यह साबित हुई थी कि हिन्दुस्तान की सरकार रोडेशिया में जो नई परिस्थिति बनी है उसमें अफ्रीका के रंगीन लोगों को हर किस्म की सहायता देना चाहती है और अंग्रेजों से भी सख्त कार्यवाही करने और अफ्रीका की जनता को मदद पहुंचाने की अपेक्षा रखती है । इस प्रस्ताव की बहस के दर्मियान सरकार की ओर से यह जो इस सदन को दिया हुआ वायदा है, इसकी पूर्ति हमारी सरकार ने कहां तक की ही, इसका खुलासा मैं जानना चाहूंगा । 11 नवम्बर 1965 से अब तक ढाई साल हो चुके हैं । इन ढाई सालों में रोडेशिया के अफ्रीकी लोगों की हालत के सुधरने की बात तो दूर रही, उनकी हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती ही गई । अभी 10-12 दिन पहले हमें यह खबर सुनने को मिली कि रोडेशिया के पांच अफ्रीकन देशभक्तों को फांसी पर लटकाने का काम गोरों (अल्प-संख्यकों) की गैर-कानूनी सरकार ने किया है । इस वक्त भी सैलिसबरी की जेलों में करीब-करीब 100 अफ्रीकन देशभक्त स्वातंत्र्य सेनानी हैं जिनको फांसी की सजा हो चुकी है । आने वाले दिनों में उनको भी फांसी पर लटकाने का खतरा है । अब तक आयन स्मिथ की सरकार का जो बर्ताव रहा है, उसको अगर एक निर्देश समझा जाये तो अगले हफ्तों और महीनों में रोडेशिया के कितने ही अफ्रीकी स्वातंत्र्य सेनानियों की हत्या होने वाली है ।

आज के इस प्रस्ताव में हम दो बातें करना चाहते हैं । पहले तो रोडेशिया में जो घटनायें इस वक्त घट रही हैं उनकी हम निन्दा करना चाहते हैं । दूसरे, हम सरकार से यह मांग करना चाहते हैं कि कामनवेल्थ से वह तत्काल बाहर आये और अफ्रीका की जनता को, खास तौर पर रोडेशिया की जनता को उनकी आजादी की लड़ाई की पूर्ति के लिये मदद देने का काम करे ।

हमें हिन्दुस्तान के अखबारों की उस खबर को पढ़कर बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही खेद हुआ जबकि उन अखबारों ने अफ्रीकी के उन स्वातन्त्र्य सेनानियों को खूनी होने का जिक्र किया । समझ में नहीं आता कि अंग्रेजों के मुकाबले में लड़ते समय भगत सिंह को पैदा करने वाला यह देश, वीर सावरकर को पैदा करने वाला यह देश, लोकमान्य तिलक को पैदा करने वाला यह देश, नेता जी सुभाष चन्द्र बोस को पैदा करने वाला यह देश जिसके अखबार और प्रचार-साधन आज इतने सड़ गए हैं कि अंग्रेजी न्यूज एजेंसी अथवा हिन्दुस्तान की न्यूज एजेंसी के कहने पर, स्वातन्त्र्य सेनिनियों को मर्डरर्स, खूनी और हर तरह की बातें छापने में इन अखबारों को कोई शर्म नहीं लगती है । रोडेशिया की सरकार और उनको मदद पहुंचाने वाली इंग्लिस्तान की विलसन सरकार, इन दोनों की तबीयत खुश हो जाय, इस किस्म का बर्ताव तो आज हमारे देश के अखबारों की ओर से हो ही रहा है, साथ ही साथ इस सरकार की ओर से भी हो रहा है ।

दुनिया के लोगों ने एक अपेक्षा की थी, 11 नवम्बर, 1965 को जब आयन स्मिथ ने रोडेशिया को स्वतन्त्र देश घोषित किया था, कि इंग्लिस्तान की सरकार की ओर से रोडेशिया के ऊपर कोई ऐसी कार्यवाही की जायेगी जिससे वहां की गैर-कानूनी अल्प-संख्यक सरकार नहीं रह पायेगी । मगर वह अपेक्षा हम लोगों की और सारी दुनिया के लोगों की पूरी नहीं हुई क्योंकि आयन स्मिथ की इस घोषणा के पहले ही इंग्लिस्तान के तथाकथित समाजवादी प्रधान मन्त्री, श्री हेराल्ड विलसन ने यह एलान किया था कि हमारी सरकार किसी भी हालत में रोडेशिया में सख्ती का इस्तेमाल नहीं करने वाली है । किसी भी हालत में वहां हम बंदूक चलाने का काम नहीं करने वाले हैं ।

17 HRS.

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात बिलकुल साफ है कि अंग्रेज रोडेशिया के अंग्रेज लोगों से नहीं लड़ना चाहते थे । अगर यही काम जो वहां आयन स्मिथ ने किया वह अगर अफ्रीका के

कोई भी रंगीन नेताओं द्वारा किया होता या अंग्रेज़ों की बसायत रहीं वहां के कोई भी रंगीन नेताओं ने किया होता तो फिर अंग्रेज़ सरकार का बर्ताव कुछ और किस्म का रह जाता ।

हम लोगों ने इस मुल्क में अंग्रेज़ों के दमन-चक्र का अनुभव किया है । आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए 1942 में गांधी जी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि 'अंग्रेज़ो ! भारत छोड़ो' और आप जानते हैं दुनिया जानती है कि उस दिन से लेकर मुल्क के आज़ाद होने तक कितने लोगों को जान की कुर्बानी देनी पड़ी और कितने लाख लोगों को जेल की यातना सहनी पड़ी । कितने लाख लोगों की ज़िंदगी को अंग्रज़ों ने उस वक्त बर्बाद कर दिया था । अदन में जो घटनाएं घटीं, केनिया में जिस किस्म का दमनचक्र चला, अफ्रीका, एशिया और दूसरे मुल्कों में अंग्रज़ों ने लोगों को आज़ादी देने से इन्कार करने के लिये जो दमनचक्र चलाया उसका मुझे यहां पर इतिहास वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उससे सभी माननीय सदस्य भली-भांति परिचित हैं । मगर एक बात को ज़रूर यहां पर दुबारा मुझको दुहराना होगा कि अंग्रेज़ अपने ही जाति भाइयों का खून बहाने के लिये किसी हालत में तैयार नहीं हैं जिसका कि सबूत हमें रोडेशिया में और उसके पूर्व दक्षिण अफ्रीका में मिल चुका है । हमने देखा है कि मुट्ठी भर गोरे लोग कई गुना ज्यादा तादाद में रहने वाले उन मुल्कों के रंगीन लोगों के ऊपर जब हर किस्म का अन्याय और अत्याचार करते हैं, इन्सानियत को उनके लिये इन्कार करते हैं और इन्सान लायक जीने के लिये उनको मौका नहीं देते हैं तब अंग्रेज़ कुछ भी अपने हाथों में हथियार उठा कर वहां लोगों को न्याय देने के लिये और गैर-कानूनी सरकारों को हटा कर वहां कानूनी सरकार बनाने के लिये बिलकुल ही तैयार नहीं हैं । मगर उपाध्यक्ष महोदय, रोडेशिया के मामले को लेकर मुझे सिर्फ अंग्रेज़ों को ही दोष नहीं देना है मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार का जो रुख रहा है, खास तौर पर अंग्रेज़ों की बसायत में बसे हुए लोगों के बारे में और अफ्रीका की जनता की आज़ादी की लड़ाई के बारे में, वह इस मुल्क के वास्ते एक बहुत ही शर्म लाने वाला रुख रह चुका है और उसी का यह एक नतीजा है जो हम लोगों को आज दस दिन के पहले केनिया में अनुभव रहा । भगत साहब वहां पहुंच गये केनिया के अध्यक्ष से मिलने । अखबारों में हमें पढने को मिला कि इस मुल्क के प्रधान मंत्री से कोई खास संदेशा लेकर केनिया और एशिया की जनता के ऊपर होने वाले जुल्म के मसले पर बात करने के लिये यह साहब वहां पर पहुंच गये मगर दुनिया के अखबारों के ज़रिये सारी दुनिया में यह शर्मनाक खबर फैल गई कि भगत साहब ने सात दिनों तक वहां इन्तज़ार किया मगर भगत साहब को मिलने के लिये केनिया के अध्यक्ष जोमो केन्याटा साहब तैयार नहीं हैं । उन्हें भारत के प्रधान मंत्री का प्रतिनिधि बना कर भेजने का क्या परिणाम हुआ ? हमारे विदेश मंत्री से मिलने के लिये उनके पास वक्त नहीं है । यह तो उसी का एक सबूत है कि हम लोगों की जो नीति रही, अफ्रीका की जनता के प्रति जिस ढंग से हम लोगों ने आज तक सरकार बनने के बाद जो रुख हम लोगों का उनके बारे में रहा है.....

MR DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member may conclude.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : अभी तो मने शुरू ही किया है ।

MR DEPUTY-SPEAKER : He has taken 17 minutes. I would like to divide the time. Of course, today we cannot conclude the debate. We started at 4.45 P.M. It will have to be continued on the next occasion. The Minister would also take about 20 minutes.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI B. R. BHAGAT) : Yes. There is an amendment.

MR DEPUTY-SPEAKER : So, the hon. Member may conclude in five minutes.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : उस मुल्क में अफ्रीकियों की सरकार बनने के बाद अफ्रीकी जनता की आकांक्षाओं के बारे में जो रुख रहा उससे इस मुल्क की सरकार के प्रति अफ्रीकी जनता में एक नफरत फैली है । वह उनकी उस नफरत का ही प्रदर्शन है जोकि उन लोगों का हमारे भगत साहब के साथ व्यवहार व बर्ताव हुआ । इस देश के शासक हमेशा इस बात को कहते हैं कि दुनिया में हिन्दुस्तान का नाम बहुत बड़ा है, हम लोगों की सेना बहुत बड़ी है, दुनिया के सामने हम लोगों की बहुत इज्जत होने की जो बात करते हुए कहते हैं कि अगर हम लोग कच्छ ऐवार्ड को अस्वीकार कर देते तो क्या कभी दुनिया में हमारी इज्जत हो सकती थी, इस तरह की झूठी इज्जत की चाह में जो यह हमारी सरकार सदा रहती है तो इस सरकार को अफ्रीका के लोगों ने, कम से कम जोमो केन्याटा ने यह बतला दिया कि दरअसल इस भारत सरकार के लिये आज अफ्रीकी जनता में क्या इज्जत है ? लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा खुद हमारी सरकार इस चीज के लिये जिम्मेदार है । इस सरकार ने अपने हाथों से यह चीज बनाई है । अब अंग्रेजों की बसायत में रहने वाले लोगों के बारे में अफ्रीकी राष्ट्रों में रहने वाले लोगों के बारे में जो बर्ताव रहा है उसके बारे में कोई नई जानकारी हासिल करने की जरूरत नहीं थी । पिछले 100 वर्ष का इतिहास इस बात को साफ बतलाता था कि अंग्रेजों ने इन लोगों को गुलाम बना कर और उन देशों का शासन करके उन देशों की जनता को इन्सान के लायक जीने का मौका नहीं देना चाहते हैं ।

इसी रोडेशिया के बारे में मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि एक तरफ तो अंग्रेज कहते हैं कि यह हम लोगों का अंदरूनी मामला है । ब्रिटिश पार्लियामेंट रोडेशिया के बारे में कानून बनाती है । ब्रिटिश पार्लियामेंट आखिरी अधिकारी है । रोडेशिया में जो कोई भी कायदा बने उस कायदे के ऊपर मुहर लगाने वाली अधिकारी सत्ता वह है । इसके लिये मैं इतना ही सबूत दूं कि सन 1923 से इंग्लिस्तान ने रोडेशिया में पूरे अधिकार, रोडेशिया के मुट्ठी भर गोरे लोगों के हाथ में दिये हैं और 1930 में रोडेशिया में वह जो लैंड एपोरशनमेंट ऐक्ट बना जिस कायदे के अनुसार अफ्रीकी जनता की जमीन को उनसे छीन करके सिर्फ गोरे लोगों को उस जमीन को दिलाने का इंतजाम किया गया । उस समय जब यह किया गया तो यह जानते हुए कि यह अफ्रीकी जनता पर बड़ा जुल्म हो रहा है तो भी हाउस आफ कामन्स ने अथवा इंग्लैंड की सरकार ने इस मसले पर कोई भी कदम उठाने का काम नहीं किया । इसलिये भले ही इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट रोडेशिया के मामले पर फैसला करने और विचार करने का अधिकार रखती हो लेकिन इतिहास यह कहता है कि कभी भी 1923 से लेकर 1968 तक कभी भी इंग्लिस्तान ने उस अधिकार का इस्तेमाल वहां की जनता के हित में नहीं किया है ।

MR DEPUTY-SPEAKER : Please try to conclude now because you have a right of reply also.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : रोडेशिया का मामला हमारे सामने सरकारी तौर पर कामनवैल्थ के एक सदस्य की तौर पर 1965 में कामनवैल्थ प्राइम मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस के वक्त आ गया था । वहां पर अफ्रीका के तमाम राष्ट्रों ने जोकि कामनवैल्थ के सदस्य हैं एक मांग अवश्य की कि चूंकि आयन स्मिथ द्वारा वहां पर एक अलग और स्वतंत्र रोडेशिया घोषित करने की सम्भावना है इसलिये इंग्लिस्तान में अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके जो पुराना संविधान रहा उस संविधान को बर्खास्त करके अफ्रीकी जनता के हाथों में सत्ता देने का प्रयास किया जाय । आज अफसोस के साथ मुझे इस बात को कहना पड़ता है कि जब इस प्रस्ताव को अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों ने कामनवैल्थ प्राइम मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में पेश किया तब हमारी सरकार ने इस प्रस्ताव का जबानी समर्थन तो जरूर

किया लेकिन उसका पूरा समर्थन करके उस सम्मेलन में एक निर्णय लेने की जो बात होनी चाहिये थी वह निर्णय लेने से इन्कार किया और श्री हेरोल्ड विल्सन की ओर से एक बयान उस सम्मेलन के बाद निकला कि इस मसले पर विचार हुआ मगर फैसला हम नहीं कर पाये । उस पर दस्तखत करने का भी एक बहुत गंदा काम हमारे प्रधान मंत्री ने उस वक्त वहां पर कर लिया । उस सम्मेलन का यहां पर जिक्र कुछ लम्बा हो गया । स्वर्ण सिंह साहब ने उसका जिक्र किया है और हम लोगों ने उस पर बहस की है लेकिन कोई भी ठोस कदम उठाने से हम लोगों ने इन्कार किया । इसलिये आज मुझे हिन्दुस्तान की सरकार पर यह आरोप लगाना है कि 1965 के पहले और 1965 के बाद रोडेशिया की जनता की आज़ादी के मामले को लेकर आपने उनको मदद करने के लिये उनकी आज़ादी को नज़दीक लाने के लिये कोई भी कदम, कोई भी ठोस कदम आपकी ओर से नहीं उठाया गया है ।

इसलिये इस प्रस्ताव को यहां पेश करते हुए मैं सरकार से यह अर्ज करना चाहता हूं कि अब यह उम्मीद छोड़ दी जानी चाहिये कि इंग्लिस्तान सरकार की ओर से या तथाकथित समाजवादी हैरोल्ड विलसन सरकार की ओर से अफ्रीका के लोगों का प्रश्न या रोडेशिया के लोगों का प्रश्न हल हो जायेगा क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इंग्लिस्तान की सरकार केन्या के इम्मिग्रेशन बिल के बारे में और जहां रंगीन देशों के लोगों का प्रश्न है वहां पर वह क्या रुख अपनाती है । वह गोरे लोगों की सरकार है । जब तक मोटे तौर पर इंग्लिस्तान में रंगीन लोग नहीं थे तब तक वह बड़ी लिबरल थी, बड़ी उदार थी, मगर आज यह मसला इंग्लिस्तान में खड़ा हो गया है, और हम लोगों ने नीग्रो और गोरे लोगों के बारे में अफ्रीका सरकार का जो रुख देखा आज वही रुख इंग्लिस्तान की सरकार अपने मुल्क में अपना रही है और विदेश नीति के बारे में भी अपना रही है ।

इसलिये हिन्दुस्तान की सरकार को आज कामनवैल्थ से बाहर आने का फैसला करना चाहिये । इसलिय ऐसा करना चाहिये कि इस कामनवैल्थ में जिन लोगों के रंग को लेकर भेद भाव किया जाता है, अगर वहां गोरी सरकार न होती तो वहां गोलियां चलतीं । लेकिन यूं कि रोडेशिया में गोरे लोगों की सरकार है इसलिये वहां गोलियां नहीं चल रही हैं । इस तरह की कामनवैल्थ में रहने का हमको कोई लाभ नहीं है, कोई जरूरत नहीं है और नैतिक दृष्टि से भी यह समर्थनीय नहीं है । इसलिये कामनवैल्थ को छोड़ आने का काम हम को तत्काल करना चाहिये ।

इसके साथ ही रोडेशिया की जनता को आज उनकी आज़ादी की लड़ाई में मदद करने के लिये मैं चाहता हूं कि भारत सरकार सबसे पहले जो मुल्क रोडेशिया में होने वाली घटनाओं की निन्दा कर रहे हैं, जो देश चाहते हैं कि रोडेशिया की जनता को आज़ादी मिलनी चाहिये, जिनके मन में ऐसी तमन्ना है, जिनकी ऐसी नीति है, उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन दिल्ली में तत्काल बुलाये । अंक्टेड के चलते हुए आप करोड़ों रुपये नाच-गाने में बरबाद करते हैं, जहां पर कुछ होने वाला नहीं है । उसकी जगह पर आप एक सम्मेलन बुलाइये, जिसमें रूस को बुलाइये, अफ्रीकी देशों को बुलाइये, एशिया के रंगीन देशों को बुलाइये, जो लोग रोडेशिया की जनता की आज़ादी की मांग करते हैं ।

संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव भारत रखे कि चूंकि ब्रिटेन ने इस मामले में पलटन भेजने से इन्कार किया है इसलिये संयुक्त राष्ट्र संघ वहां अपनी पल्टन भेजे । यूनाइटेट नेशन्स फोर्स वहां भेजे जो कि स्मिथ सरकार को हटाये और वहां की जनता के हाथों में राज्य चलाने का काम दिलाये ।

इसके बाद आखिरी सुझाव यह है कि अगर यूनाइटेट नेशन्स की मदद हम को न मिले तो भारत सरकार जिस तरह से स्पैनिश

[श्री जार्ज फरनेन्डीज़]

सिविल वार में एक अन्तर्राष्ट्रीय ब्रिगेड भेजा गया था उसी प्रकार का एक अन्तर्राष्ट्रीय ब्रिगेड बना कर और अफ्रीकी देशों की ओर से, रूस जैसे देशों की ओर से मदद लेकर वहां भेजे जो कि इयान स्मिथ की सरकार को वहां से हटा कर उस मुल्क के लोगों के हाथों में उनकी इज्ज़त, उनकी शान, देने का काम करे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव सदन के सामने पेश करता हूं।

MR DEPUTY-SPEAKER : Resolution moved :

"This House condemns the execution of freedom fighters in South Rhodesia by the illegal regime of Ian Smith and urges the Government of India to quit the Commonwealth of Nations forthwith in view of the inaction of the British Government against the illegal minority regime of Ian Smith."

There is an amendment, by Shri Bibhuti Mishra.

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संकल्प में,—

"आयन स्मिथ की गैर-कानूनी सरकार के विरुद्ध ब्रिटेन की सरकार की निष्क्रियता की दृष्टि से राष्ट्रमण्डल से तुरन्त अलग हो जाये"

के स्थान पर

यह रखा जाये—

"ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव डाले कि वह इस गैर-कानूनी सरकार को समाप्त करने के लिये सभी सम्भव उपाय करे, जिनमें सारी आर्थिक नाकेबन्दियां भी शामिल हैं, और सुरक्षा परिषद् से अनुरोध करे कि वह संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अध्याय 7 के अन्तर्गत कार्यवाही करे और दक्षिण रोडेशिया में स्मिथ शासन के विरुद्ध सभी अनिवार्य प्रतिबन्धों को लागू करे।"[1]

MR. DEPUTY-SPEAKER : The Resolution and the amendment are before the House.

We started this discussion at about 16·45 hours. At 6·30 p.m. we have to conclude the non-official business and take up the half-an-hour discussion. In any case, this resolution will be continued on the next occasion. So, the question of extending time for it just now does not arise. But from the slips that I have received I find that a number of Members would like to participate. Some time will have to be given to the Minister of External Affairs and also to the Mover for reply. So, I would suggest that as far as possible Members should not take more than five minutes each.

Now, Shri Bibhuti Mishra, a seniormost Member of the House, may begin the discussion.

श्री विभूति मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, अभी श्री फरनेन्डीज़ ने अपना संकल्प पेश किया। अगर उन्होंने मेरे संशोधन को पढ़ा होता तो मैं समझता हूं कि उनको मालूम हो जाता कि उन्होंने जो कुछ भी अपने भाषण में कहा है वह सारी चीज़ें मेरे संशोधन में आ गई हैं। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने ताकत इस्तेमाल करने की बात और उसके साथ जितनी भी और कार्रवाइयां हो सकती थीं, उन सब के बारे में कहा है। इतना ही नहीं इयान स्मिथ के स्वाधीनता की घोषणा करने के छः महीने पहले ही उससे हमारी सरकार ने सम्बन्ध तोड़ लिया। श्री फरनेन्डीज़ कहते हैं कि हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। यह बात नहीं है। जैसा मैं बतला चुका हूं जब इयान स्मिथ ने स्वाधीनता की घोषणा की उसके पहले ही हमारी सरकार ने रोडेशिया की उस गोरी सरकार से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। इसलिये हमारी सरकार ने जो भी कदम उठाया है वह ठीक ही रहा है। वह एक दम माकूल कदम उठाती रही है और इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है।

लेकिन आज जिस तरह की परिस्थिति है उसमें मैं कहूंगा कि सरकार को एक विशेष कदम उठाने की जरूरत है । जैसे कोरिया में सभी देशों की सेनायें लड़ने के लिये गईं, उसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिये कि वह सभी देशों की सेनाओं को बुला कर रोडेशिया में भेजे और वहां की गोरी सरकार को हटाने की चेष्टा करे । अगर वहां फौज भेजी जायेगी तो एक दिन भी इयान स्मिथ की सरकार टिक नहीं सकेगी । रोडेशिया में 40 लाख से अधिक आबादी है किकीयू बन्धुओं की और अंग्रेज केवल 2 लाख हैं, लेकिन यह दो लाख आदमी 40 लाख से ऊपर आदमियों को दबा रहे हैं ।

आज यू० एन० ओ० में कहां के आदमियों का प्राबल्य है ? अमरीका का प्राबल्य है और दूसरे जो उन्हीं के जाति भाई अंग्रेज लोग हैं उनका है ।

एक माननीय सदस्य : बिड़लाजी का ।

श्री विभूति मिश्र : एक माननीय सदस्य कहते हैं कि बिड़ला जी का । अमरीका बिड़ला जी ही तो है । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो समाजवादी सरकारें हैं, वह क्या कर रही हैं, रशिया क्या कर रहा है ? अगर बिड़ला जी कुछ नहीं करते तो समाजवादी लोग ही कुछ करते । न बिड़ला कुछ कर रहे हैं न समाजवादी लोग कुछ कर रहे हैं । यह सब एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं । यह चाहते हैं कि दुनिया में उनकी कालोनीज बनी रहें, और अपनी कालोनीज बना कर वह अपना व्यापार चलायें । रोडेशिया में जो दो लाख अंग्रेज हैं वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के जाति भाई हैं । ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने जाति भाइयों पर थोड़े-बहुत सैंक्शन लगाये, लेकिन उन्होंने जो भी आर्थिक सैंक्शन लगाये उनका कोई लाभ नहीं हुआ । थोड़ा-बहुत जरूर हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ कि स्मिथ दब कर कोई कार्रवाई करे ।

17.18 hrs.

[SHRI D.S. DHILLON *in the Chair.*]

110 आदमियों को स्मिथ सरकार ने पकड़ा है, जिसमें से पांच आदमियों को उसने फांसी दे दिया । 105 बेचारे जेल में पड़े हुए हैं, उनको भी फांसी होगी । इसके लिये मैं चाहता हूं कि हम लोगों ने जो कार्रवाई की है, उसके अलावा भी हमारी सरकार संयुक्त राष्ट्र में यह प्रस्ताव रखे कि.... उसके खिलाफ अध्याय सात के अन्दर फौज का इस्तेमाल किया जाये ? अध्याय 7 के अन्दर यह मैंडेटरी है कि यू० एन० ओ० को फौज का इस्तेमाल करना चाहिये । जब तक फौज का इस्तेमाल नहीं होगा तब तक अंग्रेज लोग मानने वाले नहीं हैं । आप भारत की मिसाल को ही लें । जब हम लोगों ने रेल तार काटना शुरू किया तब जाकर अंग्रेजों की आंखें खुलीं । तब जाकर उनको पता चला कि अब हम यहां पर राज नहीं कर सकते हैं । तब उनकी होश ठिकाने आई । 1942 की मूवमेंट के बाद अंग्रेज ने समझा कि अब हिन्दुस्तान से हम लोगों को जाना पड़ेगा । जब उनका आना-जाना बन्द हो गया तब उन्होंने समझा कि अब हमें भारत को छोड़ देना चाहिये । हमारी उस मूवमेंट को उन्होंने समझ लिया कि वे दबा नहीं सकेंगे । वह बनिया जात के लोग हैं । बनिया जात के ऊपर कोई मुसीबत आती है तब उसकी होश ठिकाने आती है । अंग्रेज जात का बनिया है । हमारे देश से भी वह कच्चा माल ले जाकर उसके बदले में पक्का माल यहां भेजा करता था । वहां से भी वह ऐसा ही करता था । इनके वहां पर आज भी स्वार्थ हैं । इसलिये मैं नहीं समझता हूं कि विलायत की सरकार हमारी बात को सुनेगी ।

हमारे भाई कहते हैं कि कामनवैल्थ से हट जाओ । कामनवैल्थ से हटें या न हटें, हमारी सरकार को यू० एन० ओ० में इस प्रस्ताव को रखना चाहिये और दूसरे देशों

[श्री विभूति मिश्र]

का इसके पक्ष में समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिये। जिन देशों ने स्वतंत्रता की लड़ाई भारत की तरह से लड़ी है, वे जानते हैं कि अंग्रेज इस तरह से मानने वाला नहीं है। हमारी तरह से दुनिया के और देशों ने भी स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी है। रशिया ने लड़ी है। अमरीका आज कैपिटलिस्ट देश है। लेकिन उन लोगों ने भी स्वाधीनता की लड़ाई अंग्रेज से लड़ी है। हमने लड़ी है। सीलोन, बर्मा आदि कई देशों ने लड़ी है। इस तरह के देश जो हैं उनको इसमें मदद करनी चाहिये।

एक पर्चा ब्रिटिश इनफार्मेशन सर्विस की तरफ से हम लोगों को मिला है। इसमें जो कुछ लिखा गया है, उसमें से थोड़ा-सा पढ़ कर मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इसमें एक जगह पर लिखा हुआ है :

"....while my country has constitutional responsibility for Rhodesia, we have not been able to stop actions so clearly illegal and so brutally inhuman."

इन्होंने खुद कबूल किया है कि हमने कुछ नहीं किया है--

श्री रवि राय (पुरी) : लाहौर प्रस्ताव की याद करो, मिश्र जी।

श्री विभूति मिश्र : सुनिये तो।

फिर आगे लिखा है :

" ..grave injustice has been done and that men have been kept for years in condemned cells and then denied the right of final appeal to the highest court".

इसमें यह भी लिखा हुआ है :

"As the Commonwealth Secretary said in the House of Commons, the deprivation of the right to resort to the ultimate court of appeal on a capital charge is about the grossest breach of the rule of law that we can imagine".

फांसी की सजा करते हैं। उसके लिये अपील का अधिकार नहीं देते हैं। क्वीन ने तीन आदमियों को फांसी न देने के लिये कहा था लेकिन फिर भी इन्होंने फांसी दे दी। इतना नाजायज काम ये अंग्रेज लोग कर रहे हैं कि जिसकी हद नहीं। इसका कुछ इलाज तो होना चाहिये।

आगे कहते हैं :

"Our first duty is to the prisoners in Rhodesia still under sentence of death, and new death sentences, so we hear, have been recently passed".

सब कुछ कहने के बाद कहते हैं कि हमको थोड़ा धीमा कदम उठाना चाहिये। इससे उनकी जो नीयत है उसका पता चलता है। कुछ करना भी नहीं चाहते हैं लेकिन साथ-साथ कहते हैं कि धीमा कदम हमें उठाना चाहिये। यह धीमा कदम उठाने की बात तब तक चलती रहेगी जब तक कि 105 भाइयों को फांसी पर लटका नहीं दिया जाता है।

अंग्रेज की हालत को हमारी सरकार ज्यादा अच्छी तरह से समझती है। हमारे नेता ज्यादा समझते हैं। हम सब लोग जो जेलों में रहे हैं, अच्छी तरह से उनकी हालत को जानते हैं। सारा भारत जानता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं। दुनिया में कोई भी आदमी जो कमजोर होता है उसकी बात कोई नहीं सुनता है। अगर हमारी सरकार के पास ताकत हो, हमारे पास एटम बम हो तो हमारी बात को दुनिया को सुनना पड़ेगा। हमारे पास आधुनिक फौज होती, हथियार होते तो एक दिन में अंग्रेज मान जाते। अंग्रेज के पास जितना वहां व्यापार है, तिजारत है, उसको वे बन्द कर देते और एक मिनट में ठीक हो जाते। लेकिन बीस साल के बाद भी, स्वाधीनता के बीस साल के बाद भी हमारी सरकार के पास ताकत नहीं आई है ताकि उनसे कोई बदला चुकाया जा सके या उनसे न्याय प्राप्त किया जा सके। सब लोग मौज करने वाले यहां सरकार में हैं, चाहे इधर के लोग हों या उधर के लोग हों। चाहे कांग्रेस वाले हों या कम्युनिस्ट हों, स्वतंत्र पार्टी के हों, जनसंघ वाले हों, पी० एस० पी० वाले हों, एस० एस० पी० वाले हों या कोई भी हो। मुल्क को बनाने के लिये तकलीफ सहनी पड़ती

है, लंगी लगा कर खाने के बगैर रहना पड़ता है तब जाकर कोई मुल्क आगे बढ़ता है ।

मैं चाहता हूं कि जितनी ताकत लगानी हो इन अंग्रेजों के खिलाफ आप लगायें । अंग्रेज बनिया बिना ताकत के मानने वाला नहीं है । यह बड़ा हठी है । इसकी जात बड़ी हठीली जात है । मेरे जिले में यह प्लांटर्ज के रूप में रहता था । लाचार होकर सबको वहां से भागना पड़ा । आसानी से यह नहीं गया । गांधी जी जब वहां गये या अगर कोई टोपी और छाता लेकर वहां जाता था तो उसको ये तंग करते थे । लेकिन इसको मजबूर हो कर वहां से जाना पड़ा । मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार जबर्दस्त कदम उठाये और यू० एन० ओ० में कहे कि तुमने जैसे कोरिया में फौज भेजी है उसी तरह से यहां भी फौज भेजी जाये । अगर नहीं भेजी जाती है तो यह कहा जाये कि यह समझा जायेगा कि यहां पर गोरी चमड़ी वालों का प्राबल्य है, उनका ही प्रभाव है और तुम काली चमड़ी वालों को बचाना नहीं चाहते हो । यह एक टैस्ट केस बनाया जाना चाहिये । अगर वह इसको नहीं करती है तो समझ लिया जाना चाहिये कि वह एक निकम्मी संस्था है ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : जो प्रस्ताव सदन के सामने लाया गया है इसके दो पहलू हैं । जहां तक इसका सम्बन्ध है कि रोडेशिया में क्या हो रहा है, मैं समझता हूं कि जो कुछ भी वहां हो रहा है उसकी जितनी निन्दा की जाये कम है । परन्तु वहां जो कुछ हो रहा है वही अंगोला में हो रहा है, वही साउथ अफ्रीका में हो रहा है, वही तिब्बत में हो रहा है । रोडेशिया कोई इस मामले में अलग नहीं है । आज भी संसार के अन्दर साम्राज्यवादी शक्तियां हैं, चाहे वे पश्चिम की हों या पूर्व की हों, जो लोगों पर अत्याचार कर रही हैं, जो लोगों के साथ अन्याय कर रही हैं । मैं साफ कहना चाहता हूं कि भारत की सहानुभूति वहां के इन पीड़ित लोगों के साथ है । भारत की सहानुभूति उनके साथ है जो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं चाहे वे रोडेशिया में हों या साउथ अफ्रीका में हों, अंगोला में हों या तिब्बत में हों, और इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते हैं ।

लेकिन प्रश्न यह है कि क्या सहानुभूति प्रदर्शित करने से काम चलेगा ? मैं समझता हूं कि नहीं चलेगा । हमेशा से ही और आज भी संसार के अन्दर ताकत से काम चलता है । कमजोर देशों और लोगों के लिये यू० एन० ओ० भी कुछ करने वाली नहीं है । अगर हम में ताकत होगी, उन मुल्कों में ताकत होगी जो कुछ करवाना चाहते हैं तो वे करवा लेंगे । दूर की बात को आप जाने दें । हमारे अपने मोहन रानाडे पुर्तगाल की जेल में बीस साल की कैद काट रहे हैं । उनका अपराध यह है कि उन्होंने गोआ की आजादी की लड़ाई लड़ी थी । आज वह जेल में तड़प रहे हैं और उनके साथी भी तड़प रहे हैं । यह दुर्भाग्य की ही बात है कि यहां पर उनके बारे में बोलने वाला शायद कोई नहीं है लेकिन अफ्रीका में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बोलने वाले बहुत-से हैं । मुझे इस पर आपत्ति नहीं है । वे भले उनके लिये बोलें । लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक ताकत नहीं होगी हम अपनों की भी रक्षा नहीं कर सकेंगे ।

एक माननीय सदस्य : वे भी हैं ।

श्री बलराज मधोक : अन्तर है मोहन रानाडे और अफ्रीकनों में । अफ्रीका में जहां अंग्रेज नहीं भी रहे वहां आप देख लें कि क्या हो रहा है । अभी भगत साहब केनिया से वापस आये हैं । कल वह बता रहे थे कि केनिया वैसे तो आजाद हो गया है लेकिन सारी सत्ता वहां अंग्रेज के हाथ में है और वहां पर अत्याचार हो रहे हैं । एशियन्ज पर जिनमें मुख्यतया भारतीय हैं । अंग्रेज के चले जाने के बाद आज आप देखें कि दक्षिण अफ्रीका के अन्दर भारतीयों पर अत्याचार नहीं हो रहे हैं और जगह भी हो रहे हैं । इस वास्ते समस्या का जो मूल रूप है उसको देखना होगा । मूल

[श्री बलराज मधोक]

रूप यह है कि आज संसार में भारत की साख नहीं है । भारत कमजोर देश है । हमारी सैनिक शक्ति चाहे पिछले पांच सालों में बनी है लेकिन फिर भी हमारी हालत उस आदमी की-सी है जिसके पास लाखों रुपया तो है लेकिन जिसको जनता कहती है कि दिवालिया हो गया है । कोई बैंक उसको कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है, कोई आदमी उसको कर्ज नहीं देता है । उसके मुकाबले में दूसरा वह आदमी है जो दूकान खोले बैठा है, जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन साख उसकी बनी हुई है, इसलिये दुनिया उसको कर्ज भी देती है और मान भी उसका करती है । आज हमारा देश दिवालिया है, हमारे देश की साख नहीं है । हम यहां बोलें या बाहर बोलें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई हमारी बात को सुनता नहीं है । इसका एक ही इलाज है कि भारत स्वयं बलवान बने । तब हमारी बात यू एन ओ में सुनी जाएगी तथा दूसरी जगह भी सुनी जाएगी ।

भारत को बलवान करने के लिये जो इस प्रस्ताव का जो दूसरा पहलू है उस पर हमें विचार करना होगा । हम कामनवैल्थ में रहें या निकल आएं इसको हमें देखना होगा । जब देश के अन्दर आजादी की लड़ाई चल रही थी तब मैं बहुत छोटा था । जब कांग्रेस का लाहौर सैशन हुआ उस वक्त मैं पांचवीं क्लास में पढ़ता था । उस समय एक बहस चल रही थी कि पूर्ण स्वराज्य हो या डोमिनियन स्टेट्स हो । जो आज कामनवैल्थ है यह उसी कल्पना की लीनियल डिसेंडेंट है उत्तराधिकारी । उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि डोमिनियन स्टेट्स नहीं, हम पूर्ण स्वराज्य लेंगे और हम अंग्रेज के साथ कोई नाता नहीं रखेंगे ।

उस समय गांधी जी इस मामले में नरम विचार के थे । और भी कुछ लोग उनसे सहमत थे । जो लोग भी हिस्ट्री से वाकिफ हैं, जिन्होंने स्टडी किया है, वह जानते होंगे कि अगर हम डोमिनियन स्टेट्स मान कर ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में रहना स्वीकार कर लेते तो संभव था कि भारत 1930-31 में आजाद भी हो जाता और भारत की एकता भी खत्म न होती । लेकिन उस समय हमने कहा कि हम पूर्ण आजादी लेंगे, हम इनसे कोई संबंध नहीं रखेंगे । लेकिन हुआ क्या ? देश का विभाजन भी हुआ और आजाद होने के बाद हम पूर्ण स्वराज्य को भूल गये और हम कामनवेल्थ के मेम्बर बन गये । कोई मुझे बताये कि जब अंग्रेज ने भारत का विभाजन किया था, भारत के ऊपर सब से बड़ी चोट लगाई थी, उसके बाद अंग्रेज से नाता बनाये रखने का क्या मतलब था ? क्या अन्य मुल्क जिन्होंने अंग्रेज से नाता तोड़ लिया है, क्या वह जी नहीं रहे हैं ? क्या बर्मा नहीं जी रहा है या क्या और मुल्क नहीं जी रहे हैं जिन्होंने अंग्रेज से नाता नहीं रखा ? अगर हमारी मानसिक दासता नहीं गई थी । जिनके हाथ में भारत का राज आया आजादी के बाद वह वे लोग थे कि जिनके बारे में गांधी जी कहा करते थे कि यह चाहते हैं कि अंग्रेज चला जाय पर अंग्रेजियत बनी रहे । वह अंग्रेजों के मानस-पुत्र थे । वह मैकाले के प्राडक्ट थे । इसलिये उन्होंने आजाद होने के बाद भारत को कामनवैल्थ से जोड़े रखा । उस समय कहा गया कि कामनवेल्थ का कैरेक्टर बदल गया है । कामनवेल्थ का स्वरूप बदल गया है । अब हम सब बराबर हैं । मैं मानता हूं सब बराबर हैं तो भी कभी कामनवेल्थ प्राइम मिनिस्टर्स का सम्मेलन इंग्लैंड के बाहर भी कहीं और हुआ है ? वहीं क्यों होता है ? एकाध बार कहीं कर लिया होता । और उसके बाद आज भी उसके कारण हमें जो कुछ कहते हैं कि लाभ होगा, एक लाभ यह होगा कि विजा नहीं होगा, हम कामनवेल्थ में कहीं भी घूम सकेंगे और ट्रेड के बारे में सुविधायें होंगी, वह सुविधाएं भी खत्म हो गईं और जो घटना घटी है रोडेशिया में और केन्या में और जो इंग्लैंड ने उसके बारे में रुख अपनाया है उसके बाद जो यह तर्क दिया जाता था, कामनवेल्थ में रहने के लिए वह तर्क भी खत्म

हो गया । अब कोई बताए कि कामनवेल्थ में रहने का क्या लाभ है ? हानियां बेशुमार हैं । सब से बड़ी हानि यह है कि आज भी दुनिया के बहुत-से मुल्क भारत को इंग्लिस्तान की आंखों से देखते हैं और हम भी दुनिया के बहुत-से मुल्कों को इंग्लिस्तान की आंखों से देखते हैं । हम एक आजाद देश हैं, स्वतंत्र देश हैं, हमारी भी कोई अपनी परसनालिटी है वह हम विकसित नहीं कर पाये । आज काश्मीर के बारे में अमेरिका ने वह नीति अपनायी जो अंग्रेज ने चाही । और चीजों के बारे में भी अमरीका तथा पश्चिम के बहुत-से अन्य मुल्क वह नीति बनाते हैं जो अंग्रेज बताते हैं । वह समझते हैं कि भारत के बारे में गाइड ब्रिटेन है । अगर हम कामनवेल्थ के मेम्बर न होते तो यह जो हमारे लिये जाल बिछाया था कच्छ के मामले में उसमें हम कभी न फंसते । लालबहादुर शास्त्री कामनवेल्थ सम्मेलन में गये, वहां विल्सन ने डोरे डाले और उस ऐग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करा लिये जिसका दुष्परिणाम आज हमारे सामने कच्छ एवार्ड के रूप में आ चुका है ।

इतना ही नहीं, मानसिक दृष्टि से भी कामनवेल्थ में बने रहने के कारण इस देश के ऊपर अंग्रेजी का प्रभुत्व बना हुआ है । अंग्रेजी भाषा से मुझे कोई विरोध नहीं । अंग्रेजी भाषा दुनिया की एक समृद्ध भाषा है । लेकिन इंग्लिस्तान के साथ लिंक के कारण इस देश के जीवन में जो अंग्रेजी को प्रतिष्ठा मिली है वह प्रतिष्ठा हमारे स्वाभिमान के विरुद्ध है, हमारे राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध है । यह सम्बन्ध हमें वास्तव में आजाद होने नहीं देता । अगर वह लिंक टूटे तो शायद अंग्रेजी का जो आज हमारे ऊपर प्रभुत्व है वह भी खत्म हो । इतना ही नहीं बल्कि कामनवेल्थ में बने रहने के कारण आज हमारे विदेश मंत्रालय के अन्दर भी अंग्रेजों का प्रभुत्व है । पिछले दिनों मैं बाहर गया तो कई जगह के दूतावासों ने मुझसे कहा कि हमें आपके लिये सहानुभूति है लेकिन जो आपके यहां के राजदूत हैं दे आर मोर इंग्लिश देन इंडियन, जो भारतीय दूतावासों के अन्दर राजदूत या दूसरे लोग हैं उनका जो व्यवहार है उसमें वह अंग्रेज से बढ़ कर अपने को दिखाने की कोशिश करते हैं ।

इसलिये कामनवेल्थ में रहने से जो कुछ भी थोड़ा बहुत लाभ था वह खत्म हो रहा है । कुछ लाभ मैंने कहा विजा का था कुछ ट्रेड का था । इंग्लैंड यूरोपियन कामन मार्केट में गया तो वह खत्म हो जायेगा । कामन सिटिजेनशिप का लाभ भी खत्म हो गया है परन्तु हानियां सारी बनी हुई हैं । इसलिये मेरा कहना है कि हमने पिछले 20 सालों में चाहे जो कुछ भी किया हो, अब समय आ गया है कि गम्भीरता से इस प्रश्न पर नये सिरे से विचार करें । आज देश का स्वाभिमान, देश का स्वार्थ, देश का हित और हम संसार के अंदर जो रोल अदा करना चाहते हैं वह भी इस बात का तकाजा करते हैं कि हम कामनवेल्थ से बाहर आ जायें और सही अर्थ में एक स्वतंत्र देश के रूप में खड़े हों ।

श्री विद्याधर बाजपेयी (अमेठी) : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव आपके सामने है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हूं । यह प्रस्ताव बुद्धिमत्तापूर्ण है और भारत को कामनवेल्थ से जो एक साम्राज्यवाद का प्रतीक है, सिद्धान्ततः अलग हो जाना चाहिये, इसमें दो राएं नहीं होनी चाहिएं । मालूम नहीं किस लालच में भारत आज आजादी के बाद भी कामनवेल्थ में है । शायद उसका यह ख्याल हो कि बटवारे के बाद इंग्लैंड की कुछ-कुछ हमदर्दी वह प्राप्त करे । लेकिन इतिहास बताता है कि जब-जब मौके आये हैं कामनवेल्थ ने और इंग्लैंड ने खास तौर से भारत के खिलाफ ही हमेशा फैसला किया है । उसकी हमदर्दी हमेशा पाकिस्तान से रही है । ऐसी सूरत में जब कि हिन्दुस्तान का एक उसूल सोशलिज्म का है, या तो सोशलिज्म

[श्री विद्याधर वाजपेयी]

कच्चा है और या अगर समाजवाद का सिद्धांत अपनी जगह पर स्थिर और मज़बूत है तो उसे साम्राज्यवाद से किसी तरह का संबंध स्थापित नहीं करना चाहिये और उससे पृथक् हो जाना चाहिये । यह अच्छा मौका है जब हम यह एलान करें कि हम तुमसे वास्ता नहीं रखते । जब कि अनेक रोडेशिया के फ्रीडम फाइटर्स फांसी के तख्ते पर चढ़ाये जा रहे हों और अनेकों जेल भेजे जा रहे हों, अनेकों फांसी की घड़ियों का इंतज़ार कर रहे हों, ऐसे वक्त में अगर हम यह एलान करते हैं कि हम कामनवेल्थ में नहीं रहेंगे क्योंकि तुम निकम्मे हो, तुम्हारी कोई भी पालिसी ऐसी नहीं है जिसके तहत हम रहने के लिये मजबूर हो सकें, तो यह सर्वथा उचित बात होगी । एक हुक्म देता है कामनवेल्थ रोडेशिया को कि फांसी के तख्ते पर न चढ़ाया जाय, उस हुक्म को उसने नहीं माना जो कामनवेल्थ के अन्दर है, तो ऐसे निकम्मे कामनवेल्थ के अन्दर रहने से भारत की शान कभी भी नहीं बढ़ सकती, उसकी शान घटती है । एक तरफ हम न्यूट्रेलिटी अख्तयार करते हैं और एक तरफ हम रोडेशिया से भी दोस्ती रखते हैं जो साम्राज्यवादी एक मुल्क है और अपने को हम समाजवादी कहते हैं । हम इम्पीरिअलिज्म से भी नाता रखते हैं और समाजवादी भी बनना चाहते हैं । यह हमारी समझ में नहीं आता कि यह भानुमती का पिटारा क्या है ? साफ नीति होनी चाहिये । हम मिलिटरिली बड़े मज़बूत क्यों न हों, विचारों में कमज़ोर अपने को साबित करते हैं । दुनिया के सामने कान्फिडेंस के साथ हमें अपनी बात कहनी चाहिये और उसी से हमारी बात मानी जायगी । लोच-पोच तरीके से जो मामला दुनिया के सामने पेश किया जाता है, इसी से हम कमज़ोर हैं । भारत को अपनी शान ऊंची रखनी चाहिये । कामनवेल्थ जैसे निकम्मे राष्ट्रों से हमें क्या मदद मिलेगी ? जिसकी कि क्वीन अभी तक प्रतीक है उसके साथ हम क्यों रहें ? हम पूर्ण आज़ादी के लिये लड़े थे । 14 बार मैं भी जेल गया था । इसलिये हमें कलंक है कि हमारी जो नीति है वह कमज़ोर है । हमें कमज़ोरी को त्याग देना चाहिये और अपने आपको ज़रा समझना चाहिये कि हमारा स्वरूप क्या है ? हम अपने स्वरूप को भूल गये हैं इसलिये कामनवेल्थ को देखते हैं, इसीलिये राष्ट्रसंघ को देखते हैं । राष्ट्रसंघ का भी नमूना हमने देखा । कच्छ के विवाद का फैसला हमने देखा । सब कुछ देखते हुए भी हमारी आंखें नहीं खुलीं । फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि इनसे हमें कुछ हासिल होगा । मैं समझता हूं कि इनसे हमें नाता तोड़ लेना चाहिये । अगर आज हम यह फैसला मज़बूती के साथ कर दें कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं तो कल से यह हमारी खुशामद करने लगेंगे । जब वह यह समझते हैं कि हम उनके साथ हैं, जब तक वह यह समझते हैं कि हम उनके तलवे चाटते हैं तभी तक वह हमारी अवहेलना करते हैं । हम मज़बूती से कह दें कि हम तुमको अंगूठे पर रखते हैं । तुमसे हम लड़कर आज़ादी लिये हैं, तुम्हारी मेहरबानी से हमने आज़ादी नहीं ली और तुमको हम अपने से अलग समझते हैं क्योंकि तुम कोई भी फैसला ईमानदारी से नहीं करते हो, पोलिटिकली तुम करप्ट हो, पोलिटिकली बेईमान हो और चाहे जिन मानों में भी तुम अच्छे हो । इस तरीके से भारत को अपना फैसला करना चाहिये जो उसकी मर्यादा के अनुरूप है । इन शब्दों के साथ मैं जार्ज फरनेन्डीज़ के रेज़ोल्यूशन का अक्षरशः समर्थन करता हूं ।

SHRI DHIRESWAR KALITA (Gauhati) : Mr. Chairman, I support the Resolution moved by Shri Fernandes not only because of the reason given in the Resolution but there are many other reasons. The British Government's inactivity at present to stop the hanging of patriots is not the only cause there are too many causes since 1947.

In 1947 we got our independence and on 26th January, 1950 we had our Constitution. From then onwards we are in the British Commonwealth. But what is the advantage of remaining in the British Common-

wealth? It was stated here previously that by remaining in the British Commonwealth we have got our trade advantage and we are getting many privileges by remaining in the British Commonwealth. Previously also it was argued in this House that as an independent nation we should not remain in the British Commonwealth.

The British people are very clever. It is well known. Everybody knows that the British are very clever. They have removed the word "British" from British Commonwealth and now it has become the Commonwealth of Nations. Though the word "British" is not there, everybody knows that it is the British Commonwealth.

In any meeting, who presides over the meeting? It is the British Prime Minister and not the Indian Prime Minister or the Kenya Prime Minister or the South African Prime Minister; always it is presided over by the British Prime Minister. So, it should be understood that though the word "British" is not there, it is actually the British Commonwealth of Nations and it is for their advantage that this British Commonwealth is still going on and we are there in it.

The British Government has said that the Smith Government is illegal. They passed the order of hanging. The Queen of England gave the reprieve. The Smith Government said, "We shall not obey." The British Government said that they are rebels. Yes, they are the rebel government. Against the rebel government what are the British Government doing? When the Indian people rebelled against the British Government, there was firing, hanging and killing. All kinds of force was used against the Indian people. But the British people have lost their force against this rebel government.

Why is there this double standard on the part of the British Government? Let it be understood that it is because they are their kith and kin who are ruling in Rhodesia. It is only their jugglery and demagogy in the British Parliament. This seems to be only demagogy to deceive the entire public opinion.

In that context, therefore, we must see that in no case we remain in the British Commonwealth. Shri Bhagat is sitting here. He went to Kenya. He was snubbed and dubbed; he was not even seen by anybody.

SHRI INDER J. MALHOTRA (Jammu and Kashmir) : He was not even talked to.

SHRI DHIRESWAR KALITA : He was not even talked to. And we are a member of the Commonwealth! It is a shame for us to remain a member of the Commonwealth. It was not he who was disgraced; it was our country, it was India, that was disgraced. In that context you have to see to it that we do not remain in the British Commonwealth. It is not the Commonwealth of Nations but it is the British Commonwealth.

Every year we see that defence performances are held in England. With England how can we have any defence performances! England and America are keeping imperialism alive throughout the world. We are a poor nation. In 1965 there was a war with Pakistan. What did the BBC say? Do you remember that? India was termed as the aggressor. Do we not know it? What did the British Prime Minister say then? He said that India first attacked Pakistan.

Did you protest against it in any of the Commonwealth meetings? No. From the defence point of view also, we have to understand that the British Government do not ally with us in any way in times of crises. They are against us.

Fourthly, whatever advantage is being taken is taken not by India but is taken by the British Government. Since 1947, it is to be seen that the British industry, the British investment is increasing day by day.

SHRI BIBHUTI MISHRA : English language also.

SHRI DHIRESWAR KALITA : Yes, English language also. I am sorry I cannot speak in Hindi. I can understand Hindi but I cannot speak in Hindi.

What about Assam? In Assam, the oil industry, that is, the Digboi Oil Company, which is there for hundred years is owned by British. There is the tea industry mostly owned by British. There is the coal industry mostly owned by British. Even silica mine which is a new investment is owned by

[Shri Dhireswar Kalita]

British. The River Steam Navigation Company is also British. Now they have sold it in a wretched condition to the Government when the water road is closed between India and Pakistan.

SHRI INDER J. MALHOTRA : Even half of Oil India is owned by British.

SHRI DHIRESWAR KALITA : Yes, So, by remaining in the British Commonwealth, they are increasing their investment. They are exploiting our State; they are exploiting our India; they are exploiting our Indian people. What justification is there, from the point of view of all this, that we should remain in the British Commonwealth? If any advantage is taken, it is taken by the British imperialists, not by the Indian Government, not by Indian people.

With these words, I say that the House should recommend to Government that we should quit the Commonwealth of Nations immediately.

MR. CHAIRMAN : Before I call another Member, the Secretary will make an announcement.

17·47 hrs.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY : Sir, I have to report the following messages received from the Secretary of Rajya Sabha :—

(i) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1968, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 14th March, 1968, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

(ii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation Bill, 1968, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 18th March, 1968, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

RESOLUTION *re.* QUITTING THE COMMONWEALTH—*Contd.*

SHRI BAKAR ALI MIRZA (Secunderabad) : Mr Chairman, Sir....

SHRI SHEO NARAIN (Basti) : I was the first Member to send my name.

MR CHAIRMAN : Whether you send your name or don't send your name, it is my duty to call you always. If he is angry with me, that is very bad.

SHRI BAKAR ALI MIRZA : Sir, the story of Rhodesia is a very sad story. England cannot be proud of its actions in the way in which it has functioned in Rhodesia. From all over world, the freedom-loving people have been insisting that Rhodesia cannot be helped without the use of force. Mr Wilson was adamant and he said that sanctions will be effective and that, within six months, Rhodesia will come to its knees. When further pressed, six months passed, a year passed, two years passed, even today the song sung by Mr. Wilson is that unless there is a breakdown of law and order, the force will not be used. This is a statement by Mr. Wilson. Is that not a breakdown of law and order? The Queen reprieves and Mr. Ian Smith executes the men.

The law that is enacted there on the execution of men for all kinds of offences. A man can be executed if he is in unauthorised possession of arms. These are a few offences listed. This is also added there. I quote :

> "An act likely to cause substantial financial loss within Rhodesia."

The penalty for this is hanging. When law and order has broken down, when the Queen's order has been insulted, if Mr. Harold Wilson still sticks to a particular stand, what are we, who are also members of the Commonwealth, to feel? There have been people who have been saying that we must be in the Commonwealth because we come in contact with different people, with different nations; it is not only England, but there are also Australia, Canada, New Zealand, and so on. We are not in